राज्य में अप्रैल में शुरू होगा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण

- देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग अभियान व्यापक करने के निर्देश
- एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले अफसरों से स्पष्टीकरण तलब कर कार्रवाई के आदेश
- सीईओ ने बीएलए की नियुक्ति के लिए सभी डीएम को दिए राजनैतिक दलों से दोबारा बैठक करने के निर्देश

देहरादून, 20 फरवरी (नवोदय टाइम्स) : निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में अप्रैल माह से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने यह जानकारी साझा की।

सचिवालय में शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी एसआईआर के मद्देनजर सभी जिलों की प्रशासनिक तैयारियों की जनपदवार समीक्षा कर विस्तृत जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आगामी अप्रैल माह में राज्य में एसआईआर प्रस्तावित है।



इस लिहाज से देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में मतदाताओं की मैपिंग की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप कम है। उन्होंने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन बूथों पर मैंपिग प्रतिशत कम है, संबंधित ईआरओ और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाय। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जो भी अधिकारी एसआईआर के कार्य में लापरवाही करते पाए जाएं, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी जिलों में तय समय सीमा में एसआईआर की तैयारियों के बूथ अवेयरनेस ग्रुप के गठन के निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान में 77 प्रतिशत बूथों पर बूथ लेवल एजेंट्स की तैनाती हो चुकी है। बीएलए की शत प्रतिशत तैनाती के लिए राजनैतिक दलों से पुनः बैठक सुनिश्चित करें। कहा कि एसआईआर हेल्पडेस्क के जिलों में जल्द अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी के अलावा सभी जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी, ईआरओ वर्चुअल रूप से शामिल रहे।

परिवहन सुधारों को लेकर राज्य को केंद्र से 125 करोड़ की सौगात

इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट वाहन स्क्रैपिंग नीति में प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जारी किया गया बजट

देहरादून, 20 फरवरी (नवोदय टाइम्स) : राज्य में परिवहन क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक सुधारों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य को 125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की सौगात दी है। इसमें पूंजीगत निवेश योजना (सास्की) 2025-26 के तहत 105.11 करोड़ राशि स्वीकृत है। साथ ही अप्रैल से पूर्व लागू किए गए सुधारों के लिए 20 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि शामिल है।

परिवहन विभाग के उपायुक्त शैलेश तिवारी के मुताबिक, सड़क सुरक्षा के मद्देनजर राज्य में हाई-रिस्क, हाई-डेंसिटी एवं क्रिटिकल जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट सिस्टम लागू किए गए हैं। इसके अंतर्गत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं तथा उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम एवं ई-चालान प्रणाली से इंटीग्रेट किया गया है।



> राज्य में परिवहन क्षेत्र में तकनीक आधारित सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट एवं वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन राशि राज्य में स्मार्ट एवं सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।
> – **पुष्कर सिंह धामी**, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसम्बर 2025 तक 20 स्थानों पर एएनपीआर कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं, जबकि राज्य में अब तक कुल 37 लोकेशनों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रिपल राइडिंग, ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट जैसे मामलों में प्रतिदिन औसतन पांच हजार से अधिक चालान किए जा रहे हैं।

वाहन स्क्रैपिंग नीति में प्रभावी क्रियान्वयन

उपायुक्त तिवारी के मुताबिक, वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत पुराने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों में निस्तारित करने पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नई गाड़ियों की खरीद पर विभिन्न श्रेणियों में परिवहन विभाग की ओर से रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक राज्य में अब तक 564 सरकारी एवं 5861 निजी वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। इसके लिए कुल 6425 वाहनों के विरुद्ध 9 .58 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों को दिया जा रहा बढ़ावा

राज्य में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की स्थापना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में दो एटीएस को प्राथमिक पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर 2 .5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां एएनपीआर कैमरों के माध्यम से ग्रीन सेस की वसूली की जा रही है। इस प्रणाली के तहत वाहनों को रोके बिना ही फास्टटैग वॉलेट से ग्रीन सेस स्वतः कटकर संबंधित खाते में जमा हो जाता है।

एआई समिट में कांग्रेस का हंगामा देशद्रोह : भाजपा

देहरादून, 20 फरवरी (ब्यूरो) : भाजपा ने दिल्ली में चल रहे एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे की निंदा करते हुए देश की छवि खराब करने की साजिश करार दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, दर्जनों राष्ट्राध्यक्षों के सामने देश के अपमान की ये कोशिश बताती है कि विदेशी ताकतों की टूल किट बनी कांग्रेस की ये कोशिश, संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा राष्ट्रविरोधी प्रयोग है। कहा, हम एआई के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर की तरह भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी बानगी देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठित वैश्विक एआई समिट की मेजबानी है। कहा, विश्वास नहीं होता जब दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 1000 से अधिक कंपनियों के सीईओ मौजूद हों, तब कोई नागरिक ऐसा कृत्य कर सकता है। कहा, यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम स्थल पर अनुचित व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि ठेस पहुंचाने का प्रयास है।

लोक भवन में वसंतोत्सव 27 से, तैयारियां तेज



देहरादून, 20 फरवरी (नवोदय टाइम्स) : लोक भवन में वसंतोत्सव-2026 का 'कर्टेन रेजर' आयोजित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने इस साल 27 फरवरी से लोक भवन में शुरू हो रहे तीन दिवसीय वसंतोत्सव-2026 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल विशेष पोस्टल कवर के लिए भोजपत्र का चयन किया गया है। बताया कि 27 फरवरी को दोपहर एक से शाम छह बजे तक तथा 28 फरवरी एवं एक मार्च को प्रातः नौ से शाम छह बजे तक वसंतोत्सव / पुष्प प्रदर्शनी जनसामान्य के लिए निशुल्क खुली रहेगी।

राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन में होने वाला वसंतोत्सव पिछले कुछ वर्षों में देवभूमि की सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह उत्सव प्रकृति, परंपरा और प्रगति के संगम का प्रतीक है तथा आमजन, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है।

राज्यपाल ने कहा कि वसंतोत्सव स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और कृषि आधारित उत्पादों को एक सशक्त मंच प्रदान करता है। इसके जरिए कारीगरों, किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवा उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन का अवसर मिलता है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

कहा कि पुष्प प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धित उत्पाद किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। ऐसे आयोजन पुष्प पर्यटन को प्रोत्साहित कर स्थानीय पर्यटन और रोजगार के अवसर को बढ़ा रहे हैं। सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण एसएन पाण्डेय, अपर सचिव राज्यपाल रीना जोशी, निदेशक एसएल सेमवाल थे।

अरुणाचल और मिजोरम की दिखी संस्कृति

देहरादून, 20 फरवरी (ब्यूरो) : लोकभवन में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को साकार करते कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने दोनों राज्यों के निवासियों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि भौगोलिक दूरियां हमें अलग नहीं करतीं, बल्कि हमारी विविधता राष्ट्र को समृद्ध बनाती है। उन्होंने अरुणाचल की राष्ट्रभक्ति का उल्लेख करते कहा कि वहां नमस्ते के स्थान पर 'जय हिन्द' की परंपरा गौरवशाली है। उन्होंने तवांग और परशुराम कुंड जैसी पावन कड़ियों का स्मरण किया। मिजोरम की उच्च साक्षरता दर, नागरिक बोध और 'चेराव' नृत्य की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि कि सीमांत क्षेत्रों का सशक्तीकरण ही राष्ट्र सुरक्षा की आधारशिला है।

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी साकार होगा जब हम राष्ट्र प्रथम के भाव को जीवन का मानक बनाएंगे और विविधता को विभाजन नहीं, शक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अरुणाचल प्रदेश के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक लोकनृत्य और मिजोरम के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत गीत रहे, जिन्होंने लघु भारत की जीवंत तस्वीर पेश की। मौके पर अपर सचिव राज्यपाल रीना जोशी, वित्त नियंत्रक व कार्यक्रम संचालिका डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव समेत राजभवन के तमाम अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव की मतगणना शुरू

नैनीताल, 20 फरवरी (ब्यूरो) : उत्तराखंड बार काउंसिल की 23 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिये हुए मतदान के बाद मतों की गिनती शुक्रवार से नैनीताल क्लब में शुरू हो गई है। शुक्रवार को पहले दिन अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, डीडीहाट के जिला व मुंसिफ न्यायालयों के बैलेट बाक्स खोले गए और अधिवक्ताओं द्वारा दिये गए प्रथम वरीयता मत गिने गए।

मतगणना अहमदाबाद से बुलाये गए विशेषज्ञ भवान सेठ कॉलेज ऑफ साइंसेज के प्रिंसिपल व गणितज्ञ प्रो. एचएस पटेल, रिटायर्ड प्रोफेसर बीपी ठक्कर की देखरेख में की जा रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश राम औतार भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहे। मतगणना का सीधा प्रसारण सभागार के बाहर लाउंज में लगी बड़ी स्क्रीन पर किया जा रहा है। जहां 23 सदस्यों के लिये चुनाव लड़ रहे 104 प्रत्याशी व उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही।

सरकारी स्कूलों को फ्यूचर-रेडी बनाने की दिशा में बड़ा कदम



देहरादून, 20 फरवरी (नवोदय टाइम्स) : सरकारी स्कूलों में उद्यमशीलता शिक्षा को नया आयाम देते 4000 से अधिक स्कूलों को फ्यूचर-रेडी बनाने के लिए कदम उठाया है।

स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) ने उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में जीवन कौशल एवं उद्यमिता की सोच विकसित की जाएगी। इस पहल से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक निरंतर उद्यमशील लर्निंग पाथ-वे लागू होगा। यह साझेदारी एनईपी 2020 के अनुरूप है। कक्षा 6 से 8 के लिए 'कौशल बोध' प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जो पीएसएससीआईवीई, एनसीईआरटी द्वारा विकसित गतिविधि-आधारित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें लाइफ फॉर्म, मशीन एंड मटेरियल्स तथा ह्यूमन सर्विसेस जैसे नौ मॉड्यूल्स शामिल हैं। एससीईआरटी एवं उद्यम लर्निंग फाउंडेशन प्रशिक्षण एवं क्लासरूम में सहयोग करेंगे।

रानीपोखरी में सीएसडी कैंटीन के लिए बजट जारी

देहरादून, 20 फरवरी (ब्यूरो) : डोईवाला क्षेत्र के रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों की मांग को पूरा करते सरकार ने सीएसडी कैंटीन खोलने के लिए बजट जारी कर दिया है।

सीएसडी कैंटीन खोलने को लेकर पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का आभार जताया है। जोशी से मुलाकात के दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा, सीएसडी कैंटीन न होने से जरूरी सामान के लिए दून जाना पड़ता है, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर कैंटीन की सुविधा होने से हजारों पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों के परिवारों तथा आश्रितों को बड़ी राहत मिल रही है। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा, सरकार द्वारा सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के हित में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष कमांडर एसएस मुथारु, कैप्टन आनंद सिंह राणा आदि मौजूद थे।

'सीएनजी स्टेशन के लिए भूमि मुहैया कराएं डीएम'

देहरादून, 20 फरवरी (नवोदय टाइम्स) : मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजनाओं की प्रगति एवं उनसे संबंधित चुनौतियों के समाधान को हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सभी डीएम को निर्देशित किया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को गैस पाइपलाइन और सीएनजी स्टेशन स्थापना के लिए चिह्नित स्थलों पर जरूरी भूमि उपलब्ध कराएं।

कहा, गैस कंपनियों को कार्य करने के लिए भूमि, कार्य अवधि अनापत्तियों एवं अन्य लंबित प्रकरणों का समाधान जिला स्तर पर बैठक कर जल्द किया जाए। सभी जिला पूर्ति अफसरों को सीजीडी कंपनियों के समन्वय को नोडल अफसर नामित करने और प्रगति की निगरानी को अधिकारी तैनात करने के निर्देश भी दिए। कहा, किसी भी प्रकार की अनुमति में अनावश्यक विलंब न हो। सीएस ने गैस कंपनियों के अफसरों से कहा, वे तय समय-सीमा एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कराएं। बैठक में सीजीडी कंपनियों के अफसरों ने गैस पाइपलाइन एवं सीएनजी स्टेशन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की।

अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच सीएस से मिला

अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से अंकिता के परिवार को पेयजल तक की उपलब्धता न मिलने की समस्या को लेकर मिला। बताया, उन्हें खुद ही पता नहीं कि अभी तक सरकार द्वारा अंकिता के माता-पिता को क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराई गईं हैं। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। घोषित सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर अनभिज्ञता जताई।

25 फिल्मों के लिए सरकार का अनुदान तोहफा

- 14 गढ़वाली, कुमाऊंनी जौनसारी संग 11 हिंदी अंग्रेजी फिल्में शामिल

देहरादून, 20 फरवरी (नवोदय टाइम्स) : राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 हिंदी, अंग्रेजी, कुमाऊंनी एवं गढ़वाली फिल्मों को अनुदान दिया गया।

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 फिल्मों को अनुदान धनराशि दी गई है। पिछले वर्ष जुलाई में हुई बैठक में 12 फिल्मों के प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुदान दिया गया, जबकि जनवरी 2026 में 13 फिल्मों को अनुदान दिया गया है।

इस वर्ष 8.28 करोड़ अनुदान राशि 25 फिल्मों को जारी की गई है। बताया, परिषद द्वारा फिल्म निर्माता-निर्देशकों को राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। बताया, फिल्म नीति-2024 से क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहन मिला है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी फिल्मों को अनुदान राशि जारी की गई है।

गढ़वाली फिल्मों जोना को 5,84,528 रुपये, 'मीठी' मां कु आशीर्वाद को 20,83,050, घपरोल को 21,85,819, होला जब साथ को 18,48,883, फिल्म गढ़-कुमौं को 20,93,140, असगार को 16,96,852, रतब्याण को 9,96,193, संस्कार को 26,68,175, मेरु गौ को 7,91,305, अजाण को 9,24,286, बथों सुबेरो घाम को 6,53,073, धरती म्यर कुमाऊं को 17,63,528, कारा एक प्रथा को 8,86,726 और जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट को 31,04,360 रुपये दिए गए।

हिंदी की इन फिल्मों को मिला अनुदान

विकी विद्या का वह वाला वीडियो को 1,95,00,000 रुपये, वेब सीरीज लाइफ हिल गई को 94,76,565, तानवी द ग्रेट को 99,85,806, माली को 28,01,229, मैं लड़ेगा को 15,11,907, फिफ्थ सितम्बर को 17,33,028, केसरी चैप्टर-2 को 41,22,664, ढाई आखर प्रेम का को 33,76,008, फिल्म गंगा संग रविदास को 9,34,980, ए वेडिंग स्टोरी को 9,50,302 और मिडिल क्लास लव को 51,96,578 रुपये दिए गए।

> उत्तराखंड में फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो सिस्टम से फौरन अनुमति प्रदान की जा रही है। अनुमति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। फिल्म नीति का उद्देश्य केवल फिल्मों की शूटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिल रही है। वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्मों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने को कार्य कर रही है।
> – **पुष्कर सिंह धामी**, मुख्यमंत्री

श्रीनगर में आज 100 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

देहरादून, 20 फरवरी (ब्यूरो) : प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित बाकी प्राथमिक शिक्षकों को शनिवार को श्रीनगर में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत चयनित लगभग सौ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में बेसिक शिक्षकों के 1670 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में काउंसिलिंग के बाद 1168 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें 1018 चयनित अभ्यर्थियों को पिछले माह नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र पाने से रह गए 100 चयनित शिक्षकों को शनिवार को जीजीआईसी श्रीनगर में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।

भराड़ीसैंण में बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक ने ही उठाए सवाल

- कहा, भराड़ीसैंण में गलत जगह पर बनायी गई विधानसभा

देहरादून, 20 फरवरी (नवोदय टाइम्स) : भराडीसैंण में बजट सत्र से पहले विधानसभा भवन के चयन और स्थान पर विवाद फिर गरमाता दिख रहा है। सत्ताधारी भाजपा के ही लैंसडोन विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन गलत जगह पर बनाया गया है। कहा कि यहां न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है, बल्कि अत्यधिक ठंड होती है। कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

भाजपा विधायक का कहना है कि भराड़ीसैंण विधानसभा के दौरान मंत्रियों, विधायकों और आला अधिकारियों के ठहरने व खानपान की तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन बाकी अधिकारियों, कर्मचारियों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाने से पहले सही स्थल का चयन नहीं किया गया। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन कम है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और बर्फबारी से आवागमन मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस सरकार के समय यह फैसला लिया गया था, जिसके कारण आज तक दिक्कतें बनी हुई हैं। भराड़ीसैंण की जगह यदि गैरसैंण में विधानसभा बनाई गई होती तो भी बेहतर होता। साल 2024 और 2025 में भी विधायकों ने देहरादून में ही सत्र कराने की मांग की थी, जिसे सरकार ने मान लिया था।

गौरतलब है कि कांग्रेसी शासनकाल में मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार के समय गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया और विधानसभा का बजट सत्र भराड़ीसैंण में करने का संकल्प पारित हुआ था। लेकिन, व्यावहारिक रूप से सत्र कम ही होते हैं। पिछले 12 साल में गैरसैंण में 10 सत्र आयोजित किए गए और विधानसभा कार्रवाई सिर्फ 35 दिन ही चली। कई बार तो विधानसभा सत्र दो-तीन दिन में ही समाप्त हो गया।

विधानसभा दीर्घा में 10 सचिवों की ड्यूटी

देहरादून, 20 फरवरी (ब्यूरो) : गैरसैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर मुख्य सचिव ने विधानसभा के अंदर अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहने के लिए दस सचिवों को नामित किया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सचिव रणवीर सिंह चौहान और विनोद कुमार सुमन सत्र के पहले दिन यानी नौ मार्च को अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सचिव धीरज गर्ब्याल और युगल किशोर पंत 10 मार्च को, सुरेंद्र नारायण पांडे और सी रवि शंकर 11 मार्च को, चंद्रेश कुमार यादव और पंकज कुमार पांडे 12 मार्च को और दीपक कुमार गैरोला व आनंद स्वरूप 13 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहेंगे। सभी सचिवों को कहा कि वे निर्धारित अवधि में उपस्थित रहकर चर्चा के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख बिंदुओं को नोट करना सुनिश्चित करेंगे।

'विस सत्र के लिए जल्द सूचना मुहैया कराएं'

देहरादून : ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार, शासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, विशेष प्रमुख सचिवों, सचिवों को पत्र जारी कर कहा, बजट सत्र के दौरान सीएम को चर्चाओं में भाग लेने के लिए वार्षिक योजनाओं, फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की फरवरी तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आंकड़ों संग जरूरत होगी। वार्षिक योजना के सभी सेक्टरों मसलन जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित योजना एवं बाह्य साहित्य योजनाओं के साथ फ्लैगशिप कार्यक्रमों की सूचनाओं को तैयार कर नियोजन विभाग को समय पर उपलब्ध कराया जाए। अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाएं समय पर तैयार कर सत्र से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी सूचनाओं का संकलन कर एक प्रति मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर विजय कुमार जोगदंडे और एक प्रति प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को भी मुहैया कराई जाए।

अधिकारियों के अवकाश पर लगाई रोक

देहरादून : भराड़ीसैंण में 9 से 13 मार्च तक होने वाले विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मुख्यालयों में तैनात विभागाध्यक्षों समेत सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव ने सत्र अवधि के दौरान विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी का अवकाश स्वीकृत न करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रमुख सचिवों, विशेष प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सत्र अवधि में अपेक्षित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तथा विधानसभा से संबंधित अन्य बिंदुओं पर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकारियों की मुख्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य है। सभी अधिकारी कार्यालय अवधि के बाद भी मुख्यालय पर उपस्थिति बनाए रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय संपर्क किया जा सके।

उत्तराखंड को फल पट्टी बनाने की तैयारियों पर चर्चा

देहरादून, 20 फरवरी (ब्यूरो) : मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य में फल उत्पादन को बढ़ावा देने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में फल उत्पादन को आजीविका का माध्यम बनाने के लिए गठित समिति की बैठक हुई।

उत्तराखंड को फल पट्टी के रूप में विकसित करने की दिशा में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत कीवी उत्पादन, सेब की अति सघन बागवानी योजना तथा सेब तुड़ाई के बाद प्रबंधन (सुफल) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि उच्च हिमालयी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी एवं भौगोलिक परिस्थितियां फल उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप फल प्रजातियों का चयन कर क्लस्टर आधारित एवं तकनीक समर्थित मॉडल अपनाया जाएगा। फल उत्पादन बढ़ाने को लेकर 10 क्लस्टरों का चरणबद्ध विकास करने पर जोर दिया।

pnb पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा दक्षिण दिल्ली
4वां तल, 7 पी.एन.बी. हाऊस भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली—110066 ईमेल: cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई—नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

Sr. No.	शाखा का नाम: / खाते का नाम: / उधारकर्ता/गारंटर/खाते का नाम और पता:	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / (F) मांग नोटिस के अनुसार राशि / (G) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य / (B) ईएमडी / (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	पीएनबी बी/ओ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (037110) **श्री रविंदर सिंह पुत्र यतेंद्र सिंह** प्लॉट नंबर—156—157 इकोटेक एक्सटेंशन इकोटेक प्रथम ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर यूपी—201308 **इसके अलावा: श्री रविंदर सिंह पुत्र यतेंद्र सिंह** फ्लैट नंबर—6 (दूसरी मंजिल पीछे की ओर) खसरा नंबर—346 मौजा जाखन (किशनपुर) परगना परवा दून जिला देहरादून इंदर बाबा मार्ग देहरादून **इसके अलावा: श्री. रविंदर सिंह पुत्र यतेंद्र सिंह** मकान नंबर—297 दादूपुर दनकौर गुआतमबुद्ध नगर यूपी—203201 **इसके अलावा:** श्रीमती **मधु पत्नी श्री. रविंदर सिंह** (बंधक) मकान नंबर—297 दादूपुर दनकौर गुआतमबुद्ध नगर यूपी—203201 **इसके अलावा: श्रीमती मधु पत्नी श्री. रविंदर सिंह** फ्लैट नंबर—6 (दूसरी मंजिल पीछे की ओर) खसरा नंबर—346 मौजा जाखन (किशनपुर) परगना परवा दून जिला देहरादून इंदर बाबा मार्ग देहरादून	फ्लैट नंबर—6 (द्वितीय तल, पीछे की ओर), खसरा संख्या—346, मौजा जाखन (किशनपुर), परगना परवा दून, जिला देहरादून, नगरपालिका संख्या—22/14 (पुराना संख्या—14/123), क्षेत्रफल 138.6 वर्ग मीटर, इंदर बाबा मार्ग, देहरादून, का साम्यिक बंधक, जो श्रीमती मधु पत्नी श्री रविंदर सिंह के नाम पर है।	E) 03.10.2025 F) 31.17 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 02.01.2026 H) सांकेतिक	A) रु. 74.46 लाख B) रु. 7.446 लाख C) रु. 100000/-	27.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं	श्री हरीश कुमार 8800417770

ई—नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई—नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई—नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई—नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई—400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220), द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई—नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई—नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194—1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75: जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : 20.02.2026, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

CMYK